MR. CHAIRMAN: Last Question, Mr. Joshi.

श्री जगन्नाथराव जोशी : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत से जो अमरीका में गए और वहां जा कर बसे हैं, वे लोग वहां पर जाकर बसे ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान में वृद्धि कर के वहां पर ऊंचे पदों पर हैं। मुझे अभी एक सज्जन मिले थे जो कि वहां पर ऊंचे पद पर काम करते हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत की कि उन्होंने खुद एक अपनी मंडली बनाई है और जब उन्होंने भारत सरकार से एप्रोच किया तो उनकी तरफ से उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। किन्तु आज मुझे खुशी है कि अभी मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस मामले में कुछ हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे अपने भारत के लोग वहां जाकर बसे हैं और वे अपने तकनीकी ज्ञान से, टैक्नोलोजी से, भारत की सेवा करना चाहते हैं उनके बारे में ज्यादा ध्यान आप देंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे, मैं इतना आश्वासन मंत्री महोदय से चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: The suggestion is good.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I have already replied to that part of the question.

MR. CHAIRMAN: I think the suggestion has already been replied to.

श्री जगन्नाथराव जोशी : सभापति महोदय, मैं यह सारी जानकारी देने के लिए तैयार हूं। कहिए तो आप को दे दूं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I welcome your information. Please Pass it on to me.

MR. CHAIRMAN: You better give that information to him.

Tnsser Development Programme

162. SHRI J. K. JAIN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any agreement has recently been signed between the Governments of India and Switzerland for the tusser development pro. gramme;

(b) if so, what is the estimated cost Involved in this regard;

(c) which are the States likely to be covered by the proposed programme; and

(d) which are the agencies likely to be associated in the implementation of the programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) In terms of this Agreement, Swiss Govt, grant to Swiss Franc 1 million per annum for the first 3 years with option to continue it for further 2 years will be available for this programme. The Govt, of India will provide Rs. 8 Crores for this project in the Central Plan outlay.

(c) This programme will cover 7 States, namely, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and West Bengal.

(d) The respective State governments are implementing this programme through the agencieg nominated by Khem.

श्री जे० के० जैन : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के अन्तर्गत यह स्विस टेक्नीशियंस यहां पर आकर हमारे इस उद्योग में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको कोई ट्रेनिंग भी देंगे? एक तो यह बताने की कृपा करें और दूसरा यह कि काश्मीर को इसमें क्यों नहीं लिया गया है? काश्मीर में सिल्क भारत वर्ष में बहुत ज्यादा होता है, मंत्री

महोदय ने 6 राज्यों के नाम टसर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बताए हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि काश्मीर को इसमें क्यों नहीं लिया गया है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, ट्रेनिंग की व्यवस्था इस स्कीम के अन्तर्गत है। जहां तक काश्मीर का सवाल है, ऐसे तो बहुत सारे प्रांत हैं, जहां पर थोड़ा-बहुत पैमाने पर सिल्क हुआ करता है, मगर यहां हमने इन्हीं स्टेट्स को लिया है।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, ...

MR. CHAIRMAN; Just a Minute. I will give you a chance, but let him put his second supplementary.

श्री जे० के० जैन : सभापति महोदय, क्या मंत्रालय ने कोई इस प्रकार का सर्वेक्षण किया है कि इतना रुपया खर्च होने के बाद टसर का यहां पर क्या उत्पादन बढ़ेगा और यदि उत्पादन बढ़ेगा तो उससे क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा और यदि बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और कितनी भारत को इससे आमदनी होगी ? यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, इन सारे विषयों का अभ्यास किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह सिल्क का उत्पादन बढ़ेगा और जब सिल्क का उत्पादन बढ़ेगा तो उसके साथ-साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, उसका प्रोमोशन होगा। हम आज बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट बढ़ा चुके हैं और सिल्क का उत्पादन बढ़ कर आज के पांच हजार टन से छठी योजना के अन्त तक 9 हजार टन हो जाएगा। दूसरी स्कीम्स के अन्तर्गत भी उत्पादन बढ़ाने की हमारी कोशिश है ?

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, as you are aware, Kashmir silk is the best i_n the country. In fact, Karnataka has overtaken u_s in production but, stilly the quality of Kashmir silk cocoons is the best, j would request the hon. Minister to reconsider the matter and include Kashmir also in the tusser development programme along with other States.

MR. CHAIRMAN: It is a request.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL; Sir, this scheme is applicable to tropical tusser and in Jammu and Kashmir it is oak tusser which is produced there. So, this being the position, we have accepted thi_s scheme for seven States and we have not accepted the scheme for that State. But other schemes are certainly applicable.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: For higher quality. I agree that tro-' pical is slightly coarser than the finer tusser that could be obtained from the waste of Kashmir silk cocoons. But I would request you that now that you have taken up the tusser programme for the tropical regions, you kindly take up a programme for the non-tropical regions also and include Jammu and Kashmir in it.

MR. CHAIRMAN: This is a suggestion. You may work on it.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: There are other schemes relating to it.

MR. CHAIRMAN; Now Mrs. Malhotra.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: WW the hon. Minister of Commerce be pleased to state ...

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: Sir, ...

MR. CHAIRMAN: No. She may be wearing silk mor_e than you.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: While considering the question of Kashmir, Himachal Pradesh should also be included in the plan that is being drawn up because that region is also quite suitable and has the conditions that prevail in Jammu and i Kashmir. So, if Himachal Pradesh will

also be taken into this plan, I would like the hon. Minister t° let me know.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL. I will not give an assurance *on* the floor of the House, but if anything can be done we can look into it.

श्री सदाशिव बागाईतकर : श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने एक इसका बेसिस यह बताया कि ट्रापिकल टसर के प्रोडक्शन के लिये इन स्टेट्स को लिया गया है। इसके अलावा मंत्री को क्या यह भी बतायेंगे कि जिन राज्यों का चयन उन्होंने किया है उसका आधार क्या है ?

दूसरा, मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि टसर उद्योग में खादी एण्ड विलेज कमीशन द्वारा पहले से काम किया जा रहा है और एजेंसीज की बात जो इस सवाल के आखिर हिस्से में है उसका भी उन्होंने जवाब दिया और उसमें उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि खादी एण्ड विलेज कमीशन द्वारा इस पर जो काम किया जाता था, क्या सरकार ने उसको नजर-अन्दाज कर दिया है और एजेंसीज का इस्तेमाल भी क्या सरकार करेगी ? और क्या उसको भी इस स्कीम के अन्दर स्थान दिया जायेगा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जिन प्रान्तों में यह किया जा रहा है, उनके नाम तो मैंने अभी आपको बताये हैं। बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, आन्ध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो यह अलग-अलग प्रकार की सिल्क होती है और जिस प्रकार की सिल्क जहां पर ज्यादा पैदा होती है, जिस प्रकार की सिल्क ज्यादा पैदा होने की हमको उम्मीद होती है, वहां पर हमने वैसा करने की कोशिश की है। जहां तक स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का सवाल है, मैंने अभी बताया कि इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है। स्टेट गवर्नमेन्ट्स की तरफ से अलग-अलग एजेंसीज मुकर्रर की गई है जैसे कि बिहार में डाइरेक्टारेट आफ सरीकल्चर एंड हैंडलूम की तरफ से यह काम किया जाता है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन को काम दिया है, उडीसा के अन्दर स्टेट टसर एंड सिल्क कोआपरेटिव सोसाइटी को यह काम दिया गया है, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर डाइरेक्टारेट आफ सेरीकल्चर को काम दिया गया है, महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ डेवलपमेन्ट कारपोरेशन को यह काम दिया गया है। वेस्ट बंगाल में डाइरेक्टोरेट आफ सेरीकल्चर को यह काम दिया गया है, उत्तर प्रदेश में हैंडलूम कारपोरेशन को यह काम दिया गया है। कुछ ऐसे दूसरे प्रान्त भी हैं जहां पर सिल्क के उत्पादन को बढ़ाने का काम दूसरी स्कीमों के नीचे चल रहा है। जहां तक मेरी मालूमात हैं, मैं जानता हूं कि खादी बोर्ड की तरफ से भी कुछ पैमाने पर काम होता है जैसा कि महाराष्ट्र के अन्दर है। इस प्रकार का जो काम होता है वह इस स्कीम के नीचे भी काम होता है और दूसरी स्कीम के नीचे भी होता है।

MR. CHAIRMAN: Last question, Mr. Rameshwar Singh. But do not. make it the last question for the day.

श्री रामेश्वर सिंह : ऐसा हमारे साथ न करें आप।

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस स्कीम के अन्तर्गत जहां जहां पर काम शुरू हुआ है तो क्या आपको मालूम है कि देहरादून में इस अंतर्गत काम शुरू हुआ और वहां पर जो कीड़े पाले गये थे, तो वहां पर अव्यवस्था की वजह से जो कीड़े तैयार किये गये थे उनका नाश हो गया और वे सारे

कीड़े मर गये। यह सरकार की तरफ से वहां पर जो व्यवस्था करने वाले लोग थे, उनकी लापरवाही की वजह से यह काम बंद पड़ा है। साथ ही साथ हमको यह भी बताया गया है कि बाहर से कुछ लोग टसर इम्पोर्ट कर रहे हैं। वह लोग जो मंगाते हैं, वह उसको होल्ड कर लेते हैं और वे उसकी ज्यादा कीमत लेकर 4 सौ रुपया, 5 सौ रुपया मूल्य से ऊपर लेकर ब्लैक में बेच रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : देहरादून में इस स्कीम का क्या हुआ, उसकी मालूमात आज मेरे पास नहीं है।

श्री सभापति : आप गौर करिये वहां कीड़े थे, वे मर गये।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जरूर गौर करूंगा।

श्री सभापति : मैंने उसकी सफाई कर दी कि सवाल क्या था।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Sir, you provoke him and if he starts again then what will happen? You will be a partner to this being the last question.

MR. CHAIRMAN: Mr. Rameshwar Singh and I understand each other very well.

श्री शिवराज वी० पाटिल : अब एक स्टेशन पर क्या हुआ, चूंकि बहुत सारे स्टेशन पर फैला हुआ है, इसलिए उसकी आज मालूमात नहीं है। दूसरा सवा आपका है...

श्री सभापति : पैसा ज्यादा लेकर बेचते हैं, 40–50 रुपये किलोग्राम पर।

श्री रामेश्वर सिंह : चार सौ, पांच सौ रुपये।

श्री सभापति : मैंने सोचा कि एक सिफर आपने बढ़ा दिया होगा।

श्री रामेश्वर सिंह : मेरा प्रश्न पहले समझ लें कि जिस तरह की वहां पर स्कीम चल रही है, मार्केट में शार्टेज है और आप स्विट्जरलैण्ड से उसका इम्पोर्ट कर रहे हैं तो किन-किन लोगों को आपने इम्पोर्ट करने के लिए कहा है, क्या वे लोग जो इम्पोर्ट करते हैं, उसको मंगा कर होर्ड करते हैं और होर्ड के दो तीन महीने के बाद जब देखते हैं कि मार्केट में नहीं है तो उसको बहुत हाई रेट पर बेचते हैं? क्या इस पर सरकार का ध्यान है?

MR. CHAIRMAN: Hoarding and black-marketing.

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह जो सिल्क था इसमें गये साल कुछ ऊर्जा सायल की वजह से कर्णाटक में इसके उत्पादन में कमी हो गयी थी और उसकी वजह से यहां पर कमी हुई थी। उसका भी इंतजाम बाहर से सिल्क मंगा कर किया गया है। जहां तक हो सकता है, हमारा सिल्क बाहर भेजने की कोशिश नहीं करते हैं। रा सिल्क को बजाय कपड़ा बना कर बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। मगर एक्सपोर्ट की वजह से इसमें कमी हो गई है। मेरे खयाल में यह वजह नहीं है। दूसरी जगह कमी हुई है और वह हमने पूरी की तथा आने के बाद कीमतें जो बहुत बढी थीं वे कम भी हो गयी थीं।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, ये समझ नहीं पाये हैं मेरा प्रश्न, मैंने पूछा है कि बाहर से इस तरह का सिल्क आप मंगाते हैं और वह मंगा करके कुछ लोग उसको होर्ड करते हैं। तो किन-

लोगों को आपने यह काम दिया है और जिन लोगों को दिया है, वे बाहर से जो टसर मंगाते हैं, क्या उसको होर्ड करते हैं और काफी पैसा लेकर ब्लैक में बेचते हैं, यह मेरा प्रश्न है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह हम लोगों ने मंगाया है, हमारे पास है, हमने दूसरों को नहीं दिया है। रिप्लेनिशमेन्ट स्कीम के नीचे जो भी थोड़ा-सा माल लाने को मिलता है, वह मिलता है, उस पर ब्लैक करने का सवाल नहीं है।

श्री रामेश्वर सिंह : आप किस रेट पर मंगाते हैं, किस रेट पर देते हैं। मैं बनारस में रहता हूं, हमारे सामने यह प्रश्न है बनारसी साड़ी का, आप जानते हैं कि ... (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं भी बनारस का हूं।

श्री रामेश्वर सिंह : आप रहने वाले हैं इसलिए आप मदद करें। ये किस रेट में मंगाते हैं और किस रेट में देते हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : लास्ट क्वेश्चन होगा यह समझकर जवाब देता हूं। हम लोग वहां से यहां पर जो भी मंगाते हैं, टैक्स वगैरह सब होकर चार, साढ़े चार सौ रुपया तक हम उसको देते हैं। उसकी कीमतें 6 सौ तक चली गयी थीं, 6 सौ से कम ज्यादा हो गयी थी, तो उसको कम करने के लिए हमने यह व्यवस्था की और साढ़े चार सौ के करीब बाजार भाव था, हम उसी भाव पर देते हैं।

♦63 *[Transferred to the 30th July, 1982]*

Setting up of an electronic unit by the Bharat Electronics Limited

•64. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision in regard to the setting up of an electronic unit by the Bharat Electronics Limited at the Salt Lake area in Calcutta;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, by when Government are likely to take a decision in the matter?

THE MINISTER OF DEFENCE AND HOME AFFAIRS (SHRI R. VENKATARAMAN); (a) No, Sir. As many as eleven States have evinced interest in the location of the Electronic unit in their respective! States.

(b) Does not arise.

(c) A final decision on BEL's proposal to set up two new units and the locations thereof will be taken in due course.

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE; Sir, the setting up of an electronic unit by the B.E.L. in the Salt Lake area of Calcutta is long overdue. Voluminous correspondence and reports are there. The hon. Minister says there is no proposal. But I find that our Chief Minister, Mr. Jyoti Bosu, has written at least four or five letters to the Prime Minister; the copies are with me. It started from February 25, 1980 and went up to August/ September, 1981. The first letter says: "I understand that the Electronics Commission is going to set up a research agency on the subject of electronics and this agency will be on the pattern of the Bhabha Atomic Research Centre or the Indian Space Research Organisation." I have with me all these letters and the correspondence. And the honourable Minister said there is no proposal. The